RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 02
अंक : 006
दि. 06.05.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पश्चिम बंगाल में 'कमल' खिलते ही व्हाइट हाउस से आया संदेश: राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दी बधाई

व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बीजेपी ने पांच राज्यों में हुए चुनावों में तीन राज्यों में जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत पाई है। ट्रंप ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की है।

(जीएनएस)।

वॉशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। यह जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। व्हाइट हाउस ने इसे पश्चिम बंगाल में "ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत" बताया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने क्अठर को बताया, "अभी पिछले महीने ही, अपनी फोन कॉल के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी और कहा था कि भारत कितना भाग्यशाली है कि उसे मोदी जैसा नेता मिला है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी को इस हालिया, ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत पर बधाई देते हैं।"

अमेरिकी मीडिया में भी पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में इखढ की जीत की चर्चा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है, जहां बीजेपी ने अकेले के दम पर 207 सीटों पर जीत हासिल की है। 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने लिखा है कि बीजेपी की यह जीत पहली बार है जब पीएम मोदी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह एक ऐसा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है जिस पर लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली विपक्षी तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस चुनावी परिणाम ने पश्चिम बंगाल में बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता पर पकड़ को समाप्त कर दिया है। यह पीएम मोदी के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, जिसने उनके तीसरे कार्यकाल के मध्य में उनकी स्थिति को और मजबूत किया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, "बंगाल के भाग्य में एक नया अध्याय जुड़ गया है... जनता की शक्ति की जीत हुई है और इखढ की सुशासन की राजनीति सफल हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूं।" माना जाता है देश में

बंगाल सबसे कठिन राजनीतिक मोर्चों में से एक बताया है, जिन पर पीएम मोदी ने जीत हासिल की है। विश्लेषकों का कहना है कि यह परिणाम सत्ता-विरोधी लहरऔर बीजेपी के अधिक प्रभावी चुनावी अभियान, दोनों को दशार्ता है।

'द गार्डियन' की रिपोर्ट के अनुसार, 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' के राहुल वर्मा ने इसे पार्टी नेतृत्व द्वारा चलाए गए "सात साल के प्रोजेक्ट" की परिणति बताया है। रिपोर्ट में वर्मा के हवाले से कहा गया है, "पश्चिम बंगाल में बीजेपी की उपस्थिति मजबूत और सुसंगठित थी, और मोदी को एक करिश्माई नेता के रूप में देखा जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "हिंदू वोटों के एकीकरण के बिना इस तरह का परिणाम संभव नहीं हो पाता।"

'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने कहा कि पश्चिम बंगाल लंबे समय से क्षेत्रीय और वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा है, ऐसे में बीजेपी की यह सफलता भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

'ये मोदी और शाह की जीत है', बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर विपक्षी नेता संजय राउत बोले

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बंगाल चुनाव पर

इन्होंने कहा ममता 'दीदी' को 'जिस प्रकार से हराया गया', वो लोकतंत्र की जीत नहीं है। राउत ने चुनाव आयोग को बीजेपी का गठबंधन सहयोगी बताया, आरोप लगाया कि 90 लाख वोट हटाए गए और आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। उन्होंने कहा, "जब कोई दीया बुझता है तो उसकी ज्योत बढ़ जाती है। राजनीति में ऐसी हवा चलती है। एक दिन वे लोग भी ऐसी हवा के लिए तरस जाएंगे।" संजय राउत ने कहा, "मेरा मानना है कि यह लोकतंत्र की जीत नहीं है।

यह निश्चित रूप से पीएम मोदी और अमित शाह की जीत है। जैसा कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में हुआ, लाखों मतदाताओं के नाम रक्फ़ के माध्यम से हटा दिए गए थे, और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला।"

राउत ने आगे जोड़ा, "जीत और हार के बीच 11 लाख वोटों का अंतर है। अगर 9 लाख वोट काट दिए जाते हैं, तो यह पीएम मोदी और अमित शाह की जीत कैसे हो सकती है?... मैंने पाकिस्तान, रूस और अजरबैजान में इस तरह के चुनाव देखे हैं। इस तरह का चुनाव, चुनाव भी नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमले को बताया अस्वीकार्य, तीन भारतीय हुए थे घायल

भारत ने यूएई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इधर ईरान ने इस हमले को लेकर न ही पुष्टि की है और न ही इनकार किया है।

''

ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रीज जोन पर हमला किया है, इसमें तीन भारतीय घायल हो गए हैं। भारत ने ईरान के इस हमले की निंदा की है और इन हमलों को अस्वीकार्य बताया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान शांति वार्ता ठंडे बस्ते में पड़ा है। अप्रैल में अमेरिका के साथ सीजफायर होने के बाद यूएई पर ईरान की ओर से यह पहला हमला है।

विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, 'फुजैराह पर हुआ हमला, जिसमें तीन भारतीय घायल हुए हैं, भारत को अस्वीकार्य है। हम तुरंत इस शत्रुता को खत्म करने और सीजफायर लागू करने की मांग करते हैं। भारत बातचीत और कूटनीति के रास्ते इस समस्या को हल करने की मांग करता है जिससे पश्चिमी एशिया में शांति बनी रही है।'

आगे कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय

कानून के मुताबिक होमुर्ज जलमार्ग में जहाजों के सुरक्षित आवाजाही की भी मांग करते हैं। भारत इन मुद्दों के शांति समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करता है।

इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, भारत यूएई पर किए गए हमले जिसमें तीन भारतीय घायल हुए हैं, की मैं कड़ी निंदा करता हूं। नागरिक और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है।

आगे पोस्ट में लिखा, भारत यूएई के साथ खड़ा है। भारत इस समस्या को बातचीत एवं कूटनीति के जरिए समाधान के लिए अपने समर्थन को दोहराता है। होमुर्ज जलमार्ग से सुरक्षित और निर्बाध जहाजों का निकलना क्षेत्रीय, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा के लिए बेहद अहम है।

युएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई 15 मिसाइलें और चार ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। पूर्वी अमीरात फुजैराह के अधिकारी ने कहा कि एक ड्रोन हमले में उनके ऑयल फैसिल्टी में आग लग गई, जिससे वहां काम करने वाले तीन भारतीय घायल हो गए हैं। इसके अलावा, ब्रिटिश सेना ने यूएई के तट के पास दो मालवाहक जहाजों में आग लगने की सूचना दी।

ईरान ने इस हमले को लेकर सीधे तौर पर न ही इनकार किया है और न ही इसकी पुष्टि की है। मंगलवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक्स पर कहा कि अमेरिका और यूएई दोनों को ही फिर से किसी दलदल में घसीटे जाने से सतर्क रहना चाहिए। इस घटना को लेकर ईरान की सरकारी मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरान का यूएई के ऑयल फील्ड हमला करने का कोई प्लान नहीं था।

तमिलनाडु चुनाव के बाद विजय ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, बोले-'लोगों का भला ही हमारा लक्ष्य'

"जन कल्याण ही मेरी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है", ळश्ङ चीफ विजय ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार

(जीएनएस)।

टीवीके प्रमुख विजय ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा, माननीय, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हमारे लोगों का कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जानें विजय ने और क्या कहा?

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद तमिलगा वेट्री कजगम के प्रमुख विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि "जन कल्याण ही पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है"।

एक पोस्ट साझा करते हुए, विजय ने प्रधानमंत्री को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे इस प्रयास में केंद्र सरकार के समर्थन की उम्मीद करते हैं। टीवीके प्रमुख ने लिखा, "माननीय

@पीएममोदीजी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हमारे लोगों का कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है।राजनीति से ऊपर उठकर, हम राज्य की प्रगति और तमिलनाडु के लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इस प्रयास में केंद्र सरकार के समर्थन की आशा करते हैं।"

बता दें कि टीवीके ने तमिलनाडु में शानदार शुरूआत करते हुए सोमवार को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतीं हैं। हालांकि टीवीके बहुमत के आंकड़े से पीछे है और सरकार बनाने के लिए उसे अन्य पार्टियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। 234 सदस्यीय राज्य विधानसभा में उसे बहुमत से 10 सीटें कम हैं। टीवीके सूत्रों ने बताया कि पार्टी सरकार गठन के लिए बहुमत हासिल करने हेतु आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत कर रही है।

'सनातन का अपमान करने वालों का सूपड़ा-साफ होगा', बंगाल में भाजपा की जीत पर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये परिणाम जनहित की अनदेखी करने वाले दलों के लिए कड़ा संदेश हैं. उन्होंने कहा कि विकास में भ्रष्टाचार, अपराधियों को संरक्षण और सनातन का अपमान करने वालों का सत्ता से बाहर होना तय है. योगी ने कहा कि जनता ने टीएमसी को जवाब दिया है और अब मोदी के नेतृत्व में 'सोनार बांग्ला' बनेगा.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर वहां की जनता को बधाई दी और कहा कि यह नतीजे उन दलों के लिए कड़ा संदेश है, जो जनहित की अनदेखी करते हैं. उन्होंने कहा कि जो सरकारें विकास के संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं, अपराधियों को संरक्षण देती हैं और सनातन परंपरा का अपमान करती हैं, उनका सत्ता से बाहर होना तय है. योगी ने कहा, 'जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, सनातन का अपमान करेगा, उसका सूपड़ा साफ होना तय है, बंगाल की जनता ने ये करके दिखाया है.'

सीएम योगी ने कहा, जनता ने तृणमूल कांग्रेस को करारा जवाब दिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य 'सोनार बांग्ला' की दिशा में आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अच्छी नीतियों और साफ नीयत वाली सरकार ही बेहतर परिणाम देती है, जबकि कमजोर शासन व्यवस्था का नतीजा पश्चिम बंगाल जैसा होता है.

योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश, खासकर गोरखपुर में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति से विकास तेज होता है.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. सोमवार को आए ऐतिहासिक जनादेश के बाद मंगलवार को मतों की दोबारा गिनती के रोमांचक मोड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी सीटों की संख्या 207 तक पहुंचा दी है. 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है.

मंगलवार को आए ताजा नतीजों ने इस जीत में एक और कड़ी जोड़ दी. राजड़हाट-न्यू टाउन निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष कनोडिया ने टीएमसी के मौजूदा विधायक तापस चटर्जी को महज 309 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया.

18 राउंड की गिनती के बाद कनोडिया को 1,06,564 वोट मिले, जबकि चटर्जी को 1,06,255 वोटों पर संतोष करना पड़ा. इस जीत के साथ बीजेपी की झोली में एक और सीट आ गई और टीएमसी का ग्राफ गिरकर 80 सीटों पर सिमट गया. जीत के मुख्य कारण- मोदी-शाह की रणनीतिः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और गृह मंत्री अमित शाह के सांगठनिक कौशल ने राज्य में बीजेपी की लहर पैदा की. वोट शेयर में उछालः बीजेपी का वोट शेयर 2021 के 38% से बढ़कर 45% हो गया, जबकि टीएमसी का वोट शेयर 48% से गिरकर लगभग 41% रह गया. क्षेत्रीय पैठः उत्तर बंगाल और जंगलमहल जैसे क्षेत्रों में टीएमसी का जनाधार पूरी तरह खिसक गया, जहाँ बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई.

राजनीतिक प्रभाव- 1972 के बाद यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में उसी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जो केंद्र की सत्ता में है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि बंगाल की विचारधारा और सांगठनिक ढांचे में एक गहरा बदलाव है. अब सबकी नजरें नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद की शपथ पर टिकी हैं।

मिसाइल अटैक से दहला अबू धाबी! लगातार दूसरे दिन अटैक, क्या शुरू हो गया है तीसरा विश्व युद्ध?

(जीएनएस)।

पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर है। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान की ओर से लगातार दूसरे दिन भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद यह पहली बड़ी हिंसा है।

वअए के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इन हमलों ने तेल आपूर्ति और क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

संयुक्त अरब अमीरात पर मंगलवार की रात ईरान ने फिर से हमला बोल दिया। सोमवार को हुए हमले के ठीक बाद यह दूसरा बड़ा प्रहार था। वअए के

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को 15 मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे गए थे, जिन्हें काफी हद तक इंटरसेप्ट कर लिया गया। मंगलवार को भी आसमान में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जो मिसाइलों को रोकने के दौरान हुई थीं। इन हमलों ने साबित कर दिया है कि इलाके में सीजफायर अब पूरी तरह से बेअसर हो चुका है।

तेल डिपो और जहाजों को निशाना

इन हमलों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक चोट पहुंचाना नजर आ रहा है। एक ड्रोन हमले की वजह से फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में भीषण आग लग गई, जिसमें तीन भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। इसके अलावा, ईरान ने अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी के एक खाली कच्चे तेल के टैंकर को भी निशाना बनाया, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था। इन घटनाओं से वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईरान सरकार ने सीधे तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन एक आधिकारिक बयान में इसके लिए "अमेरिका की सैन्य मनमानी" को जिम्मेदार ठहराया है।

गांधी मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल विस्तार 7 को; पीएम मोदी भी होंगे शामिल

(जीएनएस)।

पटना, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर एक बड़े सियासी फेरबदल का गवाह बनने जा रहा है। एनडीए की नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण 7 मई को होना है जिसकी तैयारी की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में जहां एक ओर शपथ ग्रहण और कैबिनेट विस्तार की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था भी की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गांधी मैदान में आमलोगों की इंट्री बंद कर दी गई है।

नए चेहरों को मिलेगी जगह

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने जा रहे इस नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिलने की चर्चा चल रही है। राज्यपाल सय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन इस समारोह की भव्यता का अंदाजा

इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। इनके अलावे इस समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तीन बड़े-बड़े मंच बनाए जा रहे हैं। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ-साथ मंत्रीमंडल में शामिल होने वाले वह सभी विधायक मौजूद होंगे। दूसरे मंच पर एनडीए के विधायक और एमएलसी के साथ अन्य बड़े-बड़े नेता रहेंगे, जबकि तीसरे मंच पर संगीत का आयोजन किया जाएगा।

तीन हेलीपेड का हो रहा निर्माण

तीन बड़े-बड़े पंडाल के साथ-साथ तीन हेलीपेड भी बनाए जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के अलावे अन्य बड़े नेता सीधे गाँधी मैदान में ही उतरेंगे। इसके लिए तीन बड़े-बड़े हेलीपैड बनाए जा रहे हैं।

सम्पादकीय

झूठ बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक सेहत पर यूएस में ही उठ रहे सवाल

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ईंरान युद्ध पर जनता को झूठ बोलने और गुमराह करने व वरिष्ठ सैन्य अफसरों को हटाने के आरोपों को लेकर प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति में सुनवाई हुई। पहली बार युद्ध शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को ईंरान युद्ध पर डेमोक्रेटिक सांसदों का सामना करना पड़ा। गत बुधवार को वो हाउस आर्म्ड सर्विसिज कमेटी के सामने पेश हुए। उनके साथ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन और रक्षा मंत्रालय के मुख्य वित्त अधिकारी जूल्स हर्स्ट भी मौजूद थे। बहस की शुरूआत हेगसेथ ने डेमोक्रेट्स और वुछ रिपब्लिकनों के बयान को निराशावादी करार देते हुए कहा कि इस तरह के कमेंट्स अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस दौरान हेगसेथ और डेमोक्रेट्स सांसदों से तीखी बहस हो गई। छह घंटे की सुनवाई में माहौल गरमा गया। संसद के निचले सदन में ट्रंप प्रशासन के 1500 अरब डॉलर के रक्षा बजट पर चर्चा के दौरान यह नोकझोक हुई। पेंटागन द्वारा युद्ध की लागत 25 अरब डॉलर बताने पर डेमोक्रेट्स भड़क गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक सेहत पर ही सवाल उठा दिए। इस पर हेगसेथ ने पलटवार किया कि ट्रंप सबसे तेज और सूझबूझ वाले कमांडर-इन-चीफ हैं। उन्होंने डेमोक्रेट सदस्यों से उल्टा सवाल किया कि क्या उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन की क्षमता पर कभी सवाल उठाए? डेमोक्रेटिक सांसदों ने अमेरिका द्वारा शुरू किए ईंरान युद्ध को वॉर ऑफ चॉइस बताया, जिसे कांग्रेस की मंजूरी के बिना शुरू किया गया। वैलिफोर्निया के डेमोक्रेट सांसद जॉन गरामेंडी ने कहा, आप और राष्ट्रपति शुरू से ही इस युद्ध के बारे में अमेरिकी जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मध्य-पूर्व के एक और युद्ध के दलदल में पंस गए हैं। हेगसेथ ने इस बयान को लापरवाह बताया और कहा कि ट्रंप किसी दलदल में नहीं हैं। आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आपकी नफरत आपको अंधा कर रही है। हालांकि कमेटी के कई रिपब्लिकन सदस्यों ने पेंटागन का समर्थन किया। फ्लोरिडा के सांसद कार्लोस जिमेनेज ने कहा कि ईंरान से अमेरिका के अस्तित्व को खतरा है। उन्होंने कहा- अगर कोई 47 साल से कह रहा है कि वह हमें मारना चाहता है तो मैं उसकी बात को गंभीरता से लूंगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और उसकी वजह से सामानों की कीमतों पर असर पर एक सांसद ने कहा : आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने मीनाब में हुए इस हमले में 168 लोग मारे गए, जिनमें करीब 110 बच्चे भी शामिल थे। आज हर अमेरिकन बढ़ती महंगाई से परेशान है। तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं और इसके जिम्मेदार आप के राष्ट्रपति और आप जैसे सलाहाकार हैं। कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य एडम स्मिथ ने कहा- हमसे गलती हुई और युद्ध में ऐसा होता है, लेकिन दो महीने तक चुप रहकर हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि हमें परवाह नहीं है। वैलिफोर्निया के भारत मूल के सांसद रो खन्ना ने इस हमले की लागत पर सवाल उठाया। इस पर हेगसेथ न कहा कि यह मामला अभी जांच के दायरे में है और वह इसकी लगात पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब्स ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक सेहत पर सवाल किया। इस सवाल पर पीट हेगसेथ और सारा जैकब्स के बीच तीखी बहस हुई। खबर है कि विपक्षी डेमोक्रेट्स सदस्यों ने हेगसेथ के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव भी लाने का पैसला किया है। इस प्रस्ताव के आने के बाद ईंरान जंग में ट्रंप और हेगसेथ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने 5 गंभीर आरोप लगाते हुए हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने का पैसला किया है। रक्षा मंत्री को वैबिनेट से हटाने के लिए सीनेट और हाउस में 2 तिहाई सांसदों की जरूरत होगी।

वेस्ट यूपी में सियासी समीकरण को मजबूत करेंगे सीएम योगी, 7-11 तक दिखाएंगे दम

सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम करते दिखेंगे। 7 से 11 मई तक का कार्यक्रम तय हो चुका है।

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल को चुनाव के साथ गरमाने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को सेट किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी विधानसभा चुनाव की प्रयोगशाला बनती जा रही हैं। सभी सियासी दल यहां चुनावी रण में कूदने की तैयारी में जी जान से जुटे हैं। देश के पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ , पूर्व सीएम अखिलेश यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री, सूबे के मंत्री, पूर्व मंत्री और सभी दलों के संगठन के पदाधिकारी रणनीति के तहत वेस्ट को सियासी तौर पर बेस्ट बनाने की जुगत में हैं। अब मिशन 2027 पर निकले सीएम योगी वेस्ट यूपी में सियासी चाल को फिर रफ्तार देने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सात मई को सहारनपुर के देवबंद में जनसभा करेंगे। वहां वे विकास कार्यों की सौगात देंगे। 11 मई को बागपत जिले का दौरा लगभग तय हैं। ऐसा कर सीएम सहारनपुर और मेरठ मंडल को साधने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 13 मई को मथुरा में आमजन की सियासी नब्ज टटोलेंगे।

वेस्ट से होता रहा है अभियानों का आगाज

दरअसल, 2014, 2029 और 2024 के लोकसभा, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट यूपी से ही चुनावी बिगुल फूंका था। इसी तरह कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा के अखिलेश यादव, बसपा की मायावती और उनके बड़े पदाधिकारी, आजाद मसाज पार्टी के चंद्रशेखर, एआईएमआईएम के असददुदीन औवेसी समेत सभी राजनीतिज्ञ वेस्ट से वोट हासिल करने के लिए दस्तक देकर मौहाल बनाते रहे हैं।

अमित शाह ने सभाली थी कमान

2014 के लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए तो बाकायदा मौजूदा गृहमंत्री और भाजपा के लिए चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कमान संभाली थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन को मुद्दा बनाकर अमित शाह ने खास वोट बैंक को एकजुट किया था। उसके बाद मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल समेत तमाम दिग्गज यहां सिसासी दांव चलते रहे हैं।

इस बार भी पीएम, सीएम के साथ उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह लगातार वेस्ट यूपी में सक्रिय हैं। तेज गर्मी के बाद भी जिलों में रैली और बड़ी सभा कर रहे हैं।

अब योगी की दस्तक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित वेस्ट यूपी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला और पार्टी का संगठन सतर्क और सक्रिय हो गया है। सात मई को सहारनपुर जनपद के देवबंद में मुख्यमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सहारनपुर-मुजफ्फरनगर राज्य मार्ग पर स्थित सिल्वर पैराडाइज के पास मैदान का चयन किया है। साफ-सफाई और जमीन को समतल करने का काम तेजी से किया रहा हैं।

सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। वाहनों की पार्किंग के लिए मंडी समिति परिसर को चिन्हित किया गया है। देवबंद से विधायक और योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री जनसभा के दौरान जनपद की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

इसी के साथ मुख्यमंत्री का 11 मई को बागपत जनपद के भगवानपुर नांगल गांव स्थित शिव गोरखनाथ आश्रम में नवनाथ मूर्ति का अनावरण समारोह में जाना प्रस्तावित है। वह गौरीपुर गांव में नंदन कानन उद्यान का उद्घाटन कर सकते हैं। अधिकारियों ने आश्रम का निरीक्षण भी कर लिया। माना जा राह है सीएम दोनों जगह 2027 के लिए सियासी जमीन तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मथुरा में डिप्टी सीएम की धमक

मथुरा जिले के फरह के परखम स्थित दीनदयाल गो-विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में 13 मई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान छात्रावास, पशु चिकित्सालय, हर्बल गार्डन सहित कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का उद्घाटन होगा। उनके साथ निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज और कथा मर्मज्ञ विजय कौशल महाराज भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के एक प्रदेश स्तरीय नेता का कहना है कि आने वाले वक्त में अब पूरी फोकस यूपी पर रहेगा।

8 साल पहले ही सरकार बना चुके थे थलापति? अब तमिलनाडु में असली 'राज तिलक'!

(जीएनएस)।

तमिलनाडु की राजनीति में 'विजय' शब्द अब सिर्फ सिनेमाघरों का नहीं, बल्कि विधानसभा का भी हकीकत बन चुका है। थलापति विजय की मात्र दो साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेट्टी कझगम (TVK) ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीत ली हैं। बहुमत से सिर्फ 10 सीट कम, लेकिन इतिहास रचने के लिए काफी। 7 मई को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।

लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि एक अभिनेता मात्र दो साल में सत्ता तक पहुंच गया। सबसे दिलचस्प यह है कि यह सब 8 साल पहले उनकी ही फिल्म 'सरकार' (2018) की कहानी से मेल खाती है। आइए जानते हैं असल में क्या था फिल्म में?

2018 में रिलीज हुई फिल्म 'सरकार' एआर मुरुगदॉस के निर्देशन में बनी थी। ₹110 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹253 करोड़ का कारोबार किया था। विजय के साथ कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी सरथकुमार मुख्य भूमिकाओं में थीं। योगी बाबू, तुलसी और राधा रवि ने यादगार किरदार निभाए थे।

फिल्म का हीरो सुंदर रामास्वामी (विजय) एक सफल ठफक्ष बिजनेसमैन है। वह सिर्फ वोट डालने के लिए भारत लौटता है। लेकिन पोलिंग बूथ पर पहुंचकर पता चलता है कि उसका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया है। यहीं से शुरू होती है कहानी, चुनावी धोखाधड़ी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ एक आम आदमी की जंग।

फिल्म के अंत तक सुंदर रामास्वामी न सिर्फ अपने वोट की लड़ाई लड़ता है, बल्कि पूरे भ्रष्ट तंत्र को चुनौती देता है। वह पेशेवर

राजनेताओं के खिलाफ खड़ा होता है, अपनी कंपनी से इस्तीफा दे देता है और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है। शुरूआत में लोग उसे 'कॉर्पोरेट वाला' कहकर हंसते हैं। लेकिन एक जोरदार भाषण में वह अपना सफर सुनाता है, मछुआरे के बेटे से बड़े बिजनेसमैन बनने तक का संघर्ष, गरीबी से अमीरी तक का सफर। उस भाषण के बाद जनसमर्थन का सैलाब आ जाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स ठीक वैसा ही है, जैसा तमिलनाडु चुनाव के नतीजों में हमने देखा। एक सिस्टम-चेंजर का उदय। आज जब थलापति विजय ळश्ङ के बैनर तले 108 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो फिल्म के संवाद और सीन रियल लगने लगे हैं।

टत्र्क्र से लेकर विजय तक, द्रविड़ राजनीति का नया अध्याय

तमिलनाडु में यह पहली बार नहीं है जब कोई सुपरस्टार राजनीति में आया हो। एमजी रामचंद्रन (टत्र्क्र) ने 1972 में अक्षअउटङ की स्थापना की और 1977 से 1987 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी सिनेमा से सीधे सत्ता तक का सफर तय किया था। अब 51 साल के थलापति विजय उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक फर्क के साथ। टत्र्क्र की पार्टी को बनाने में दशकों लगे, जबकि ळश्ङ को सिर्फ दो साल हुए हैं।

विजय ने राजनीति में आने का ऐलान 2024 में किया था। कोई पुराना संगठन नहीं, कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ एक नई पार्टी और युवाओं-महिलाओं का भरोसा। 2026 के चुनाव में ळश्ङ ने उटङ के पारंपरिक गढ़ को तोड़ा, अक्षअउटङ-इखढ गठबंधन को पीछे छोड़ा और 108 सीटों पर कब्जा कर लिया।

फिल्म 'सरकार' में भी सुंदर रामास्वामी ठीक यही करता है, बिना किसी पुराने सिस्टम के, नई सोच के साथ सत्ता की लड़ाई। फिल्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग थी, रियल लाइफ में ळश्ङ का मेनिफेस्टो भी महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए आकर्षक वादों से भरा था कि ₹2500 मासिक भत्ता, 6 फ्री छढ्रॠ सिलेंडर, 8 ग्राम सोना जैसी स्कीम्स। दोनों जगह एक ही थीम, सिस्टम को बदलो, सत्ता को जनता के पास लाओ।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और अक्षअउटङ के वर्चस्व वाले राज्य में ळश्ङ की ये जीत सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है। यह नई राजनीति की जीत है, जहां सिनेमा का करिश्मा, युवाओं का जोश और महिलाओं का समर्थन मिलकर पुरानी पार्टियों को पीछे छोड़ गया।

उटङ का 'वुमेन कार्ड' फेल हो गया, इखढ गठबंधन बिखर गया, जबकि ळश्ङ ने महिलाओं को 23 टिकट दिए और 13 जिता दिए। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म 'सरकार' में सुंदर रामास्वामी ने आम लोगों को अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाया।

तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई पार्टी सिर्फ दो साल में 108 सीटें जीतकर सत्ता के करीब पहुंच गई है। 7 मई को जब थलापति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो न सिर्फ तमिलनाडु, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति की दिशा बदल जाएगी।

8 साल पहले 'सरकार' फिल्म में विजय ने स्क्रीन पर जो सपना दिखाया था, आज उसी को रियल लाइफ में जी रहे हैं। थलापति अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि तमिलनाडु के सबसे युवा और सबसे चर्चित मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।

बीच समंदर फंसा अमेरिकी जहाज, न निकलने का रास्ता, न पीछे हटने की जगह

(जीएनएस)।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरानी न्यूज एजेंसी 'फार्स' के मुताबिक, अमेरिका के दो व्यापारिक जहाज इस इलाके के पथरीले और उथले पानी में फंस गए हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं।

जहां अमेरिका इन जहाजों के सुरक्षित गुजरने का दावा कर रहा है, वहीं ईरान की सेना (IRGC) इसे खारिज कर रही है। इलाके में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और सीजफायर टूटने की खबरों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है।

ईरानी मीडिया का दावा है कि ओमान के तट के पास का समुद्री रास्ता काफी खतरनाक और उथला है। यहां बड़ी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी जहाज न तो आगे बढ़ पा रहे हैं और न ही पीछे हट पा रहे हैं। ईरान के अनुसार, भौगोलिक रूप से यह हिस्सा जहाजों के निकलने लायक नहीं है। फिलहाल अमेरिका ने अपने जहाजों के फंसने की खबरों पर चुप्पी

साध रखी है, जिससे सस्पेंस और गहरा गया है।

पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की शुरूआत की थी, जिसके बाद से तनाव और बढ़ गया। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने न केवल इजरायल और अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बनाया, बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' को भी बंद करने की चेतावनी दे दी है।

पाकिस्तान की कोशिशों से अप्रैल की शुरूआत में दोनों पक्षों के बीच एक संघर्ष-विराम (सीजफायर) हुआ था। उम्मीद थी कि बातचीत से कोई हल निकलेगा, लेकिन इस्लामाबाद में हुई चर्चा बेनतीजा रही। हालांकि ट्रंप ने इस सीजफायर को आगे बढ़ाया था, लेकिन सोमवार को ईरान द्वारा वअए पर किए गए हमले ने शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब इस क्षेत्र में दोबारा बड़ी जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे संकरे लेकिन व्यापार के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देता है या यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। फिलहाल ईरान की सेना इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।

विश्व अस्थमा दिवस पर विशेष अस्थमा से बढ़ती मौतें और इनहेलर की सुलभता का संकट

प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को 'विश्व अस्थमा दिवस' का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। यह उन करोड़ों लोगों की जीवनशैली और स्वास्थ्य चुनौतियों को रेखांकित करने का एक वैश्विक मंच है, जो हर दिन एक-एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इस वर्ष 'द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा' (जीआईएनए) द्वारा निर्धारित विषय 'अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजनरोधी इनहेलर की

उपलब्धता, अभी भी एक अत्यावश्यक आवश्यकता है' स्वास्थ्य जगत के समक्ष एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। यह विषय सीधे तौर पर उस विसंगति पर प्रहार करता है, जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के बावजूद एक बड़ी आबादी को जीवनरक्षक इनहेल्ड कॉंटिकोस्टेरॉइड्स जैसी बुनियादी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अस्थमा एक ऐसी दीर्घकालिक बीमारी है, जो पेफड़ों के वायुमार्ग को प्रभावित करती है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है और वे संवुचित हो जाते हैं। इस स्थिति में मरीज को सांस लेने में भारी कठिनाई, सीने में जकड़न, लगातार खांसी और घरघराहट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विडंबना यह है कि अस्थमा के उपचार के लिए प्रभावी चिकित्सा मौजूद होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों का आंकड़ा डरावना है। वर्तमान वैश्विक सांख्यिकी के अनुसार, दुनियाभर में 33 करोड़ से अधिक लोग इस व्याधि से जूझ रहे हैं और हर साल लगभग 4.61 लाख लोग इसके कारण काल के गाल में समा जाते हैं।

भारत के संदर्भ में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है क्योंकि विश्व की वुल अस्थमा मौतों का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत में दर्ज होता है जबकि भारत में मरीजों की संख्या लगभग तीन करोड़ के आसपास है, फिर भी मृत्यु दर का इतना ऊंचा होना हमारी स्वास्थ्य प्रणालियों और जागरूकता के स्तर पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

अस्थमा की गंभीरता को समझने के लिए इसके शारीरिक तंत्र को जानना आवश्यक है। जब कोई अस्थमा रोगी किसी 'ट्रिगर', जैसे धूल, धुआं या प्रदूषण के संपर्व में आता है तो उसके वायुमार्ग की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

वायुमार्ग के चारों ओर की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और आंतरिक परत में सूजन आ जाती है, जिससे बलगम का निर्माण बढ़ जाता है। यह प्रयिा पेफड़ों में हवा के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, जैसे वह एक संकरी नली के माध्यम से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो।

केजरीवाल का बड़ा दावा: पंजाब में प्रो-इंकम्बेंसी, मान सरकार से जनता बेहद खुश, फिर से सरकार बनाने को बेताब

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के साथ दिल्ली आए पार्टी के विधायकों के साथ कपूरथला हाउस में संवाद किया। उन्होंने कहा कि चार साल बाद भी पंजाब में प्रो-इंकम्बेंसी है। भगवंत मान सरकार के कामों से लोग बेहद खुश हैं और फिर सरकार बनाने के लिए बेताब हैं।

पंजाब में मुफ्त बिजली, 10 लाख का इंश्योरेंस, शानदार सड़कें, पिंडों में 3100 खेल के मैदान, खेतों तक नहरी पानी पहुंच रहा। पंजाब में पहली बार इतने काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पंजाब में रोका गया था और अब भी भाजपा का विजय रथ पंजाब के लोग रोकेंगे। पंजाब के छह राज्यसभा सांसद भाजपा ने चोरी की है। पंजाब के लोग इसका बदला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लेंगे।

ॅ्रेस्र१३८

राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर कपूरथला हाउस पहुंचे पंजाब के "आप" विधायकों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में "आप" की सरकार बने 4 साल हो गए हैं। अब विधानसभा चुनाव के महज 10 महीने बचे हैं। चुनाव के आखिरी साल में ऐसा बहुत कम सरकारें होती हैं कि उस राज्य के

लोग अपनी सरकार की तारीफें कर रहे हों।

कहा जाता है कि चार साल बाद एंटी इंकम्बेंसी (सत्ता विरोधी लहर) बहुत हो जाती है। लेकिन 4 साल बाद आज पंजाब के हर पिंड व मोहल्ले में एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो-इंकम्बेंसी है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पंजाब के लोग दिल से पंजाब सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पंजाब में 44 हजार किलोमीटर शानदार सड़कें बन रही हैं। अब तक 9 हजार किमी सड़कें बन चुकी हैं और अगले एक-दो महीने में सारी सड़कें बन जाएंगी। इतनी शानदार सड़कें आजतक पंजाब में कभी नहीं बनीं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के शहरों में गली-गली के अंदर सड़कें व गलियां बन रही हैं। सोमवार को सीएम भगवंत मान ने पिंडों में शानदार 250 खेल के मैदान का उद्घाटन किया है। पंजाब ने देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए। अच्छे खिलाड़ी तब निकले, जब सरकारें उनकी कोई मदद नहीं करती थीं। हम मान सरकार हर पिंडों में शानदार खेल के मैदान बना रही है। पंजाब के 3100 गांवों में शानदार खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इसके अलावा, 6 हजार गांवों के अंदर समान्य खेल के मैदान बनेंगे। इस तरह पंजाब के हर गांव के अंदर बच्चों को खेल का मैदान मिलेगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी गंदे तालाबों की सफाई करा दी गई है। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी भेजा जा रहा है। किसानों को खेती की जरूरत के लिए दिन में बिजली मिलने लगी है। पिछली सरकारों में रात के 3 बजे बिजली आती थी और किसान को रात में जागने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

बिजली मुफ्त हो गई, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, जल्द ही महिलाओं को हजार रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इतने सारे काम अब तक पंजाब में किसी भी सरकार ने नहीं किया। पिछले सरकार हमेशा कहती थी कि खजाना खाली है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि खजाना खाली है, क्योंकि हमारी ईमानदार सरकार है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पूरे देश में बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। भाजपा ने जनतंत्र को हाइजैक कर लिया है, जनतंत्र की हत्या कर दी है। पूरे देश में कोई भी पार्टी जीत कर आ जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये ईडी-सीबीआई और पैसे से उस पार्टी के विधायक तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, जेल भेज देते हैं और सरकारें गिरा देते हैं।

जीतने के लिए ये लोग वोट काट देते हैं, अपना वोट जोड़वा देते हैं। सोमवार को पश्चिम बंगाल चुनाव का आया परिणाम कोई चुनाव नहीं था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर तांडव चल रहा है। इसी तरह इन्होंने बिहार, महाराष्ट्र में किया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल गया, उससे पहले नई दिल्ली विधानसभा में 1 लाख 48 हजार वोट थे। जब मैं लौट कर आया तो 1 लाख 6 हजार वोट बचे थे। इन्होंने करीब 6 महीने के अंदर 42 हजार वोट कटवा दिया। पिछली बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैं 30 हजार वोट से जीता था।

इन्होंने 42 हजार वोट कटवा दिए और इस बार मैं 3 हजार वोट से हार गया। विपक्ष कैसे जीत सकता है, जब उसके सारे वोट कटवा देंगे। आज पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज देश के जनतंत्र के उपर संकट है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी पर सकंट खड़ा हो गया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मई 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। उस दौरान 'मोदी जी की आंधी' चल रही रही थी। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड समेत जहां भी चुनाव हुए ये लोग जीतते चले गए। फिर फरवरी 2015 में दिल्ली का चुनाव हुआ और 70 में से सिर्फ 3 सीट भाजपा की आई।

उन्होंने कहा कि जब भगवान श्रीराम अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने अपना अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा कि यह घोड़ा जहां जाएगा, वो भगवान राम की जमीन हो जाएगी। भगवान श्रीराम के दोनों बच्चों लव-कुश के मंदिर अमृतसर में है। जब वहां भगवान श्रीराम का घोड़ा पहुंचा, तो दोनों बच्चों ने घोड़े को रोक लिया। तब से कहा जाता है कि अश्वमेघ का घोड़ा रोकने वाले लव-कुश थे। इसी तरह, आम आदमी पार्टी और दिल्लीवालों ने 2015 में मोदी जी का अश्वमेघ घोड़ा रोका था। वरना मोदी जी का घोड़ा चलता जा रहा था।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी भी मोदी जी की आंधी चल रही है। ये लोग असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली जीत गए। हर तरफ जीतते जा रहे हैं, अगले साल फरवरी में पंजाब के चुनाव होंगे। पंजाब में न सिर्फ मोदी जी का अश्वमेघ घोड़ा रूकेगा, बल्कि पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी और पंजाबी ही मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा। यह मेरा दिल कहता है। ये सब कैसे होगा, मुझे नहीं पता है। आम आदमी पार्टी पंजाब तो जीतेगी। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। घर-घर जाकर पंजाब के लोगों को बताना होगा कि भाजपा पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब के लिए एक भी काम नहीं किया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र में इनकी सरकार है। आरडीएफ में पंजाब सरकार को डबल पैसा दे देते, लेकिन ये लोग पंजाबियों का हक भी छिन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार बनी तो पंजाब का सारा पानी हरियाणा को दे देंगे।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

'मैं हारी नहीं, इस्तीफा नहीं दूंगी', ममता के बयान पर सीएम की रेस में शामिल सुवेंदु अधिकारी क्या बोले?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनके इस बयान के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे विधानसभा चुनावों के बाद की राजनीतिक तनातनी बढ़ गई।

अधिकारी, जिन्होंने हाल ही में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी, ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बनर्जी के इस्तीफे से इनकार वाले बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "संविधान में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।" उनका यह बयान ममता बनर्जी के रुख पर सीधा पलटवार माना जा रहा है।

दरअसल, ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब उनसे राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने दो टूक कहा कि वह "लोकभवन नहीं जाएंगी" और किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगी।

बनर्जी ने अपनी हार को जनादेश का परिणाम मानने से साफ इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया, "हम पब्लिक मैंडेट से नहीं बल्कि एक साजिश से हारे हैं। मैं हारी नहीं।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "वो संवैधानिक नियमों के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं।" उन्होंने बीजेपी पर "अत्याचारों" का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी।

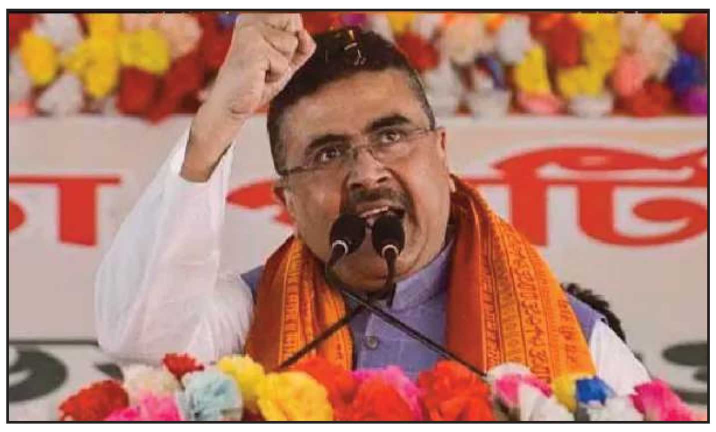

चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा "हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं था बल्कि चुनाव आयोग से था।" ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में काम किया, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया, "इस बार काउंटिंग में चोरी हुई है। सभी कैंडिडेट्स पर बुरी तरह हमला किया गया। सभी काउंटिंग एजेंट्स पर उक्त्रक्र और उफ्द्क्रने बुरी तरह हमला किया और उन्हें बाहर निकाल दिया। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। काउंटिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी पर एक बेरहम हमला है। उन्होंने काउंटिंग में सब कुछ लूट लिया है।"

भाजपा बोलीं- ममता बनर्जी का बयान कॉन्स्टिट्यूशनल ईशनिंदा है

ममता बनर्जी के इन कड़े बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया कि बनर्जी हिंसा के रास्ते से संवैधानिक व्यवस्था को "शॉर्ट-सर्किट" करने का सुझाव दे रही हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के सरासर खिलाफ है।

पूनावाला ने लिखा, "ममता बनर्जी जो सुझाव दे रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन-विरोधी, अंबेडकर-विरोधी है और चुनाव के बाद का गुस्सा होने के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल ईशनिंदा भी है। वो पावर के शांतिपूर्ण ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को पलटना चाहती हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की पहचान है।"

सीएम योगी के कड़े रुख के बाद यूपी में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था खत्म, अब आयोग ने 24 घंटे में मांगा जवाब

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद भले ही पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, लेकिन उसने मीटर को लेकर उठ रहे सवालों का विद्युत नियामक आयोग को 10 दिन की तय अवधि में जवाब नहीं दिया। 10 के बजाय 20 दिन में भी जवाब न मिलने को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने अब 24 घंटे में कारपोरेशन प्रबंधन से जवाब तलब किया है। माना जा रहा है कि आयोग, प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस बीच उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी कार्यालय आदेश जारी करने की मांग की है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधी तमाम शिकायतों को देखते हुए उपभोक्ता परिषद ने पिछले महीने आयोग में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर आयोग ने 16 अप्रैल को कारपोरेशन प्रबंधन से 10 दिन में जवाब मांगा था। ऐसे में 26 अप्रैल तक प्रबंधन को जवाब देना था लेकिन अब तक आयोग में जवाब दाखिल नहीं किया गया।

आयोग ने कारपोरेशन प्रबंधन की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अब अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को 24 घंटे में पूरे मामले पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि जवाब न देने पर आयोग दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। जवाब न देने पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि पावर कारपोरेशन, विद्युत अधिनियम 2003 की की धारा 47(5) तथा भारत सरकार एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है।

वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों को आयोग द्वारा जारी कास्ट डाटा बुक के अनुरूप ही काम करना चाहिए लेकिन राज्य में नियमों के विरुद्ध नये बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड मोड में देने तथा मौजूदा पोस्टपेड कनेक्शनों को उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड में बदला गया है। परिषद अध्यक्ष ने आयोग से मांग की है कि कारपोरेशन प्रबंधन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जेल से छूटे हिस्ट्रीशीटर की लखनऊ में हत्या, दो दिन बाद प्लॉट में बरामद हुआ शव

लखनऊ के अवध विहार योजना में हिस्ट्रीशीटर सचिन यादव की सिर कूचकर हत्या कर दी गई, जिसका शव एक निजी स्कूल के पीछे खाली प्लॉट में मिला।

(जीएनएस)। लखनऊ। शहीद पथ के किनारे स्थित अवध विहार योजना में हिस्ट्रीशीटर 30 वर्षीय सचिन यादव की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए स्कूल के पीछे खाली प्लाट पर फेंक दिया गया। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने दुर्गंध आने पर देखा तो पुलिस को सूचना दी।

सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज रिषभ यादव ने बताया कि सचिन हत्या के प्रयास के मामले में बंद था। दो हफ्ते पहले जेल से छूटा था। दो दिन पहले दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद से गायब था। सचिन के भाई की हत्या पड़ोसियों ने छह महीने पहले कर दी थी।

अवध विहार योजना सेक्टर आठ में एक निजी स्कूल के पीछे मंगलवार दोपहर युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस पहुंची लोगों की मदद से शव की पहचान की कोशिश की। पता चला कि शव विजयनगर नीलमथा रेउतापुर के रहने वाले सचिन यादव का है।

इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने साक्ष्य संकलन किए। सचिन के दाहिनी ओर कनपटी के पास सिर पर चोट का निशान मिला। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि सचिन के खिलाफ पीजीआई समेत कई थानों में मारपीट, जानलेवा हमला, एससीएसटी एक्ट समेत छह से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

वह पीजीआई थाने से हिस्ट्रीशीटर था। गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। कुछ दिन पहले जेल गया था। दो हफ्ते पहले ही जेल से छूटा था। सचिन के घरवालों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटनास्थल को जाने वाले मार्ग पर लगे सीसी कैमरों की पड़ताल की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य बता रहे हैं कि बदमाशों ने सचिन की हत्या किसी अन्य स्थान पर की। इसके बाद रात अथवा तड़के बदमाशों ने शव स्कूल के पीछे मुफीद स्थान पर फेंका गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम को मौके से किसी संघर्ष के साक्ष्य आदि नहीं मिले हैं। मौके से सचिन का कोई मोबाइल फोन आदि भी नहीं मिला है।

इंस्पेक्टर ने बताया कि सचिन का पड़ोसी विजय यादव और उसके परिवारीजनों से विवाद चल रहा था। छह माह पूर्व दिवाली के आस पास सचिन के छोटे भाई सोनू यादव की भी गोली मार कर हत्या की गई थी। मामले सचिन की ओर से विजय के परिवारीजनों और उसके नाबालिग भतीजे पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। विजय की ओर से सचिन और उसके पिता समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मामले में डेढ़ हफ्ते पहले सचिन जेल से जमानत पर छूटा था। सचिन के पिता अभी जेल में ही हैं।

विनेश फोगाट को क्यों मिला एंटी-डोपिंग एजेंसी का नोटिस? वापसी से पहले पहलवान के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती

(जीएनएस)। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर चर्चा में हैं लेकिन इस बार मामला कुश्ती के दांव-पेच का नहीं बल्कि नियमों की अनदेखी से जुड़ा है। अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी आईटीए ने विनेश को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया है कि उन्होंने अपना एक डोपिंग टेस्ट मिस कर दिया है।

यह घटना 18 दिसंबर 2025 को हुई है जब डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर विनेश द्वारा बताए गए स्थान पर उन्हें टेस्ट के लिए नहीं ढूंढ पाया। नियम के मुताबिक एलीट एथलीटों को हर दिन एक घंटे का ऐसा समय और स्थान बताना होता है जहां वे बिना किसी नोटिस के टेस्ट के लिए उपलब्ध रह सकें।

विनेश ने क्या जवाब दिया था?

विनेश ने इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया था कि उस दिन वह हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ में थीं। साथ ही उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और छोटे बच्चे का हवाला भी दिया था। हालांकि आईटीए ने उनके तर्कों को पूरी तरह पर्याप्त नहीं माना। एजेंसी का कहना है कि अगर विनेश के कार्यक्रम में बदलाव हुआ था तो उन्हें मोबाइल ऐप या ईमेल के जरिए अपनी लोकेशन तुरंत अपडेट करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। इसी लापरवाही के कारण आईटीए ने इसे विनेश की पहली आधिकारिक विफलता के रूप में दर्ज किया है।

विनेश के लिए चेतावनी

राहत की बात यह है कि यह विनेश के लिए केवल एक चेतावनी है और इसे एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन नहीं माना गया है। वाडा और अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ के नियमों के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी एक साल के भीतर तीन बार अपनी लोकेशन बताने में फेल होता है या टेस्ट मिस करता है तभी उस पर दो साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। चूंकि यह पिछले 12 महीनों में विनेश की ऐसी पहली गलती है इसलिए उनके करियर पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। विनेश को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 4 मई से सात दिन का समय दिया गया है।

कुश्ती में वापस आ रही हैं विनेश

यह पूरा घटनाक्रम विनेश के कुश्ती में दोबारा वापसी के ठीक बाद सामने आया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था लेकिन दिसंबर 2025 में उन्होंने दोबारा मैट पर लौटने का फैसला किया। वापसी के साथ ही वह कड़े डोपिंग टेस्ट के घेरे में आ गई हैं। इस समय वह गोंडा में होने वाले नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट के जरिए अपनी नई शुरुआत करने जा रही हैं जहां उनकी सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर भारतीय कुश्ती संघ ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है।

सुप्रीम कोर्ट में अब 34 नहीं, बल्कि इतने होंगे जज! केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

(जीएनएस)। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश (उखक) सहित जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है, जिसे अब बढ़ाकर 38 करने की योजना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार आगामी संसदीय सत्र में एक विशेष विधेयक पेश करेगी।

जजों की संख्या में यह 12% की वृद्धि मुख्य रूप से अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।

कैबिनेट का नया फैसला

सरकार का यह निर्णय न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कार्यरत हैं। 4 नए पद सृजित होने से संवैधानिक पीठों के गठन और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। संसद से विधेयक पारित होने के बाद यह बदलाव आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा, जिससे न्याय प्रक्रिया की बाधाएं दूर होंगी।

जजों की संख्या का इतिहास

1956 में मूल कानून के तहत जजों की संख्या केवल 10 निर्धारित थी। वक्त के साथ मुकदमों का अंबार बढ़ा, तो इस संख्या को भी बढ़ाया गया। 1960 में इसे 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 किया गया। साल 2009 में जजों की संख्या 30 तक पहुंचाई गई। पिछली बार 2019 में एक संशोधन के जरिए संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 (मुख्य न्यायाधीश के अलावा) किया गया था। यह क्रमिक विस्तार बढ़ती जनसंख्या और कानूनी पेचीदगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है।

नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम सिस्टम' का पालन किया जाता है। यह एक विशेष समूह होता है जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। यही समूह नामों पर विचार करता है और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। सरकार की जांच के बाद, अंतिम मुहर राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जजों के चयन में निष्पक्षता और योग्यता को प्राथमिकता दी जाए।

योग्यता और कार्यकाल

सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सख्त मापदंड तय हैं। उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसे किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहने का अनुभव हो, या उसने 10 साल तक वकील के रूप में वकालत की हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता (कानून का जानकार) भी हो सकता है।

लखनऊ के इस नवाब ने शुरू किए थे बड़ा मंगल पर भंडारे, 200 साल से आज भी जारी है यह परंपरा

(जीएनएस)। ज्येष्ठ माह के मंगलवारों को बड़ा मंगल कहा जाता है। पूरे लखनऊ में इन दिनों में भंडारे आयोजित होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन भंडारों की शुरुआत मुस्लिम नवाब ने की थी। ज्येष्ठ माह के मंगलवारों को 'बड़ा मंगल' के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत, खासतौर पर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में इस दिन का विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व है। हनुमान जी को समर्पित यह दिन आस्था, सेवा और एकता का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि बड़ा मंगल पर भंडारा कराने की परंपरा की शुरुआत करीब 200 साल पहले अवध के नवाब मोहम्मद वाजिद अली शाह ने की थी, जो आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है।

बड़ा मंगल क्यों होता है खास?

ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी माह में भगवान राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इसके साथ ही, यह भी कहा जाता है कि इसी समय हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा, व्रत और दान का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय और भक्ति से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

कैसे शुरू हुई भंडारे की परंपरा?

बड़ा मंगल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा अवध के नवाब मोहम्मद वाजिद अली शाह से संबंधित है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले उनके पुत्र की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कई वैद्यों और हकीमों के प्रयासों के बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ, तब किसी ने नवाब की बेगम को सलाह दी कि वे लखनऊ के अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना करें।

लखनऊ की पहचान बन गया बड़ा मंगल

आज के समय में बड़ा मंगल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सेवा का बड़ा उदाहरण बन चुका है। लखनऊ में इस दिन जगह-जगह भंडारे लगाए जाते हैं, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर सेवा करते हैं। सड़क किनारे शरबत, पानी, पूड़ी-सब्जी और प्रसाद का वितरण किया जाता है। तपती गर्मी में लोगों को ठंडा जल और भोजन देना पुण्य का कार्य माना जाता है।

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

बड़ा मंगल की सबसे खास बात यह है कि यह त्योहार सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर इस परंपरा को निभाते हैं। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा शुरू की गई यह पहल आज भी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनी हुई है। यह दिन बताता है कि आस्था और मानवता का रिश्ता किसी एक धर्म से बंधा नहीं होता है।

हनुमान जी की होती पूजा

बड़ा मंगल के दिन भक्त हनुमान जी का व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं, चोला चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं। साथ ही, जरूरतमंदों को भोजन और जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इस तरह बड़ा मंगल केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और एकता का ऐसा संगम है, जो सदियों से लोगों को जोड़ता आ रहा है।

भक्ति के साथ प्रकृति की जिम्मेदारी भी जरूरी.. बड़े मंगल पर लखनऊ में दिखा अनूठा नजारा

(जीएनएस)। लखनऊ में बड़े मंगल का नजारा हर साल खास होता है.. भक्ति, भीड़ और भंडारों की भरमार. लेकिन इस बार तस्वीर में एक नया एंगल जुड़ गया. लखनऊ में बड़े मंगल का नजारा हर साल खास होता है.. भक्ति, भीड़ और भंडारों की भरमार. लेकिन इस बार तस्वीर में एक नया एंगल जुड़ गया. शहर में 'वॉटर वूमन' के नाम से पहचानी जाने वाली शिप्रा पाठक ने इस धार्मिक आयोजन को पर्यावरण से जोड़ते हुए एक अलग ही पहल शुरू कर दी.

इस बार बड़े मंगल पर शहर में करीब 55 हजार हरे पत्तलों का वितरण किया गया. प्रेस क्लब से लेकर हजरतगंज, हनुमान सेतु, इंदिरानगर और गोमती नगर तक कई भंडारों में प्लास्टिक की जगह ये हरे पत्तल नजर आए. लोगों के लिए यह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश था कि भक्ति के साथ प्रकृति का भी ध्यान रखें.

'वॉटर वूमन' क्यों बना चर्चा का केंद्र?

शिप्रा पाठक को लोग 'वॉटर वूमन' इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लंबे समय से जल संरक्षण और नदी बचाने से जुड़े अभियानों में सक्रिय रही हैं. इस बार उन्होंने बड़े मंगल जैसे बड़े आयोजन को चुना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंच सके. उनका फोकस साफ था.. अगर भंडारों से प्लास्टिक हटेगा, तो शहर की नालियों और नदियों में जाने वाला कचरा भी कम होगा.

गोमती को बचाने की चिंता भी साथ

इस पहल का सबसे अहम पहलू रहा गोमती नदी को लेकर जागरूकता. हर साल भंडारों के बाद भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा नदी तक पहुंचता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है. लोगों को समझाया गया कि प्लास्टिक में गर्म खाना परोसना सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और पर्यावरण के लिए भी.

सिर्फ वितरण नहीं, जागरूकता भी

यह अभियान सिर्फ पत्तल बांटने तक सीमित नहीं रहा. भंडारों में पहुंचकर आयोजकों और श्रद्धालुओं से सीधे बातचीत की गई, उन्हें प्लास्टिक के नुकसान बताए गए और वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. कई जगह लोगों ने खुद आगे बढ़कर कहा कि अब से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे.

हर मंगलवार चलेगा अभियान

इस पहल को लगातार जारी रखने की तैयारी है. अब हर मंगलवार को हरे दोना-पत्तलों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, ताकि यह एक आदत बन सके, सिर्फ एक दिन का प्रयोग नहीं. विशेषज्ञों के मुताबिक, हरे पत्तल पूरी तरह जैविक होते हैं और आसानी से नष्ट हो जाते हैं. वहीं प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है और जमीन व पानी दोनों को नुकसान पहुंचाता है.

छोटी पहल, बड़ा संदेश

बड़े मंगल जैसे बड़े आयोजन में यह पहल दिखाती है कि अगर सही समय और सही जगह पर बदलाव शुरू किया जाए, तो उसका असर दूर तक जाता है. इस बार लखनऊ में सिर्फ प्रसाद ही नहीं बंटा, बल्कि एक सोच भी बंटी— 'भक्ति के साथ प्रकृति की जिम्मेदारी भी जरूरी है.'

कैबिनेट बैठक में बोले पीएम मोदी, बंगाल में जीत का लंबे समय से था इंतजार, सत्ता के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सभी मंत्रियों और नेताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और मेहनत का परिणाम बताया.

कैबिनेट बैठक में बोले पीएम मोदी, बंगाल में जीत का लंबे समय से था इंतजार, सत्ता के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पार्टी के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि इस जीत का लंबे समय से इंतजार था और यह केवल पार्टी की नहीं, बल्कि जनता की जीत है.

लंबे समय से इसका इंतजार

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सभी मंत्रियों और नेताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और मेहनत का परिणाम बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और इस जनादेश का सम्मान करना बेहद जरूरी है.

इसके साथ ही, मोदी ने अपने

सहयोगियों को यह भी याद दिलाया कि सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है. उन्होंने कहा कि अब सभी को मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास, सुशासन और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करना चाहिए, ताकि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके.

बंगाल चुनाव बड़ी उपलब्धि

एक दिन पहले यानी सोमवार को बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हृआज से बंगाल भयमुक्त हुआ हैहृ और अब राज्य में बदलाव का समय है, बदले का नहीं. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे हिंसा की राजनीति को छोड़कर राज्य के भविष्य और विकास पर ध्यान दें.

मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों में पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा, डर और जान-माल के नुकसान के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ और यह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है. प्रधानमंत्री ने अपने लगभग 50 मिनट के भाषण में यह भी कहा कि बंगाल अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां हृभय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए.हृ

उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जीत के बाद बदले की भावना नहीं, बल्कि विकास और सुशासन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. इसके अलावा, मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन (संशोधन) विधेयक का विरोध करने की उन्हें हृकड़ी सजाहृ मिली है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी को भी भविष्य में महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है.

'अब ऐसा डॉक्टर कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा'; सीएम योगी ने जब सांसद रवि किशन की ली चुटकी

गोरखपुर के एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सांसद रवि किशन की चुटकी ले ली। मानद उपाधि को लेकर उन्होंने चुटकी ली।

(जीएनएस)।

गोरखपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन की एक बार फिर चुटकी ली। उन्होंने रवि किशन को मिले डॉक्टरेट की मानद उपाधि पर ऐसा बयान दिया कि कार्यक्रम में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मजे लेते देखे। दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर गोरखपुर जिले में आयोजित 'शिक्षामित्र सम्मान समारोह' को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने इस दौरान सशक्त शिक्षा समृद्ध उत्तर प्रदेश का संकल्प जताया। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। सीएम योगी ने इस मौके पर डॉक्टरेट की उपाधि पर किसी न देखने और प्रोफेसर न लिखने की भी सलाह दे दी।

सीएम योगी ने क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे सांसद रवि किशन ने मुझसे कहा कि हमें बधाई नहीं दिए। मैंने पूछा, किस बात की बधाई। उन्होंने कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है। हमें मानद उपाधि है, अब मैं प्रोफेसर लिखूंगा। हमने इनसे कहा कि अरे आप प्रोफेसर लिख नहीं

सकते। यह तो मानद उपाधि है। आप उसे लेकर कहीं भी जाएंगे तो आपको उसके नाम पर नौकरी भी नहीं मिलेगी।

सीएम योगी ने चुटीले अंदाज में कहा कि आप केवल उस मानद उपाधि को लगा सकते हैं। आप अपने गले में टांग कर घूम सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं अब डॉक्टर लिखूंगा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा डॉक्टर बन करके कहीं उपचार करने चले गए तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा?

शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि की बात

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों के गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का मामला गरमाया। उन्होंने कहा कि यह नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी। इस प्रकार का प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी शिक्षामित्र की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था यह डेढ़ लाख परिवार सड़कों पर भटकने की नौबत नहीं आने देना है, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक सेवा दी थी। करीब 18-19 वर्षों से वे सेवा कर रहे थे।

सीएम योगी ने कहा कि हमने सोचा, उम्र के इस पड़ाव में कहां जाएंगे। उस समय तत्कालीन डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने मुझसे कहा कि यह बड़ा संकट होगा क्या किया जा सकता है? हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम उनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे। शिक्षामित्रों का मानदेय साढे. तीन हजार रुपये से बढ़ाकर कि हमने 2017 में 10,000 रुपये में करने का फैसला लिया। हम चाहते थे कि समय-समय पर इसमें कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी हो।

सीएम योगी ने बिचौलियों का जिक्र करते हुए कहा कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूली बात आ गए थे, जिन लोगों ने आपका शोषण किया। आपके साथ न्याय न हो, इसके लिए विपक्षी दलों के षडयंत्र का शिकार बनाया। जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार की बात को समझे। सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी। हम आपके सहयोग करना चाहते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,45,000 शिक्षामित्रों को सरकार ने सीधे 18,000 रुपये का मानदेय देने का निर्णय लिया है। अप्रैल माह से ही इसका भुगतान कर दिया गया है।

रवि किशन को मिली है मानद डिग्री

एलएनसीटी यूनिवर्सिटी की ओर से गोरखपुर सांसद को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होने के बाद गोरखपुर आगमन पर एम्स गोरखपुर में निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता एवं डॉक्टर्स ने सांसद का स्वागत किया। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर की पावन धरती का स्नेह और सम्मान प्राप्त होना अत्यंत भावुक और गर्व का विषय है। इसके लिए उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं उपस्थित लोगों का हृदय से आभार जताया।

सीएम नायब सिंह पर महिला से अभद्रता के आरोप, अनुराग ढांडा बोले- जब रक्षक ही ऐसे तो बेटियां कैसे सुरक्षित?

(जीएनएस)।

हरियाणा में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह पर एक महिला पत्रकार से अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है।

ढांडा का कहना है कि जब प्रदेश के मुखिया पर ही ऐसे आरोप लगें, तो आम महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यह मामला अब केवल एक व्यक्तिगत आरोप नहीं, बल्कि हरियाणा की गिरती कानून-व्यवस्था और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है।

मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप और राजनीतिक घमासान

अनुराग ढांडा के ट्वीट ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह पर एक महिला पत्रकार की कलाई पकड़ने का आरोप लगाते हुए उनकी नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। ढांडा का तर्क है कि यदि सार्वजनिक मंच पर एक रसूखदार महिला सुरक्षित नहीं है, तो राज्य की आम बेटियों का क्या हाल होगा? विपक्ष इसे सत्ता के अहंकार और महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता का प्रतीक बताकर सरकार पर हमलावर है।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े

हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में हर दिन औसतन 19 महिलाएं किसी न किसी अपराध का शिकार हो रही हैं। साल 2023 में दर्ज हुए 1,800 रेप के मामले यह बताने के लिए काफी हैं कि अपराधी बेखौफ हैं। ढांडा का कहना है कि जब रक्षक ही सवालों के घेरे में हों, तो इन आंकड़ों में सुधार की उम्मीद करना बेमानी लगता है।

गैंगस्टर कल्चर और कमजोर कानून-व्यवस्था

हरियाणा में केवल महिला अपराध ही नहीं, बल्कि संगठित अपराध भी तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य में 80 से अधिक सक्रिय गैंग और 300 से ज्यादा गैंगस्टरों की मौजूदगी ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन वाले इन अपराधियों के कारण व्यापारियों और आम जनता में डर का माहौल है। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका है।

पुलिस बल की कमी और सिस्टम की नाकामी

राज्य में बढ़ते अपराधों के पीछे एक बड़ा कारण पुलिसकर्मियों की भारी कमी भी है। हरियाणा पुलिस में लगभग 30% पद खाली पड़े हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। 2021 से 2024 के बीच अपहरण के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, जिसका सीधा असर प्रदेश की शांति और सुरक्षा पर पड़ रहा है।

जनता के मन में असुरक्षा का गहराता डर

महिला पत्रकार का यह बयान कि "जो सीएम सरेआम हाथ पकड़ सकते हैं, वह पर्दे के पीछे क्या करते होंगे," लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यह डर केवल उस पत्रकार का नहीं, बल्कि हरियाणा की हर उस महिला का है जो घर से बाहर निकलती है। अनुराग ढांडा ने इसी डर को आवाज देते हुए पूछा है कि क्या हरियाणा की भाजपा सरकार बेटियों को सुरक्षित माहौल देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है?

एयरपोर्ट पर अवैध रूप से पकड़ा गया 12 करोड़ की कीमत का गांजा, बैंकॉक से आए यात्री को इस तरह दबोचा

लखनऊ में बैकॉक से आए एक यात्री के पास से 12 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद किया गया। मामले की जांच जारी है।

(जीएनएस)।

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) की टीम ने एक यात्री के पास से भारी मात्रा में करीब 12 करोड़ रुपये कीमत की हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया है।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक सोमवार को डीआरआई विभाग को खुफिया सूचना मिली कि बैंकॉक से रात 10:35 बजे लखनऊ पहुंचने वाली एयर एशिया की फ्लाइट (एफडी-146) से आ रहे एक यात्री के पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ मौजूद है।

इस सूचना पर डीआरआई विभाग की टीम लखनऊ एयरपोर्ट पर मुस्तैद हो गई और बैंकॉक से पहुंचे इस विमान के यात्रियों की गहनता से जांच शुरू कर दी। तभी एयरपोर्ट बिल्डिंग में जांच के दौरान उक्त विमान से आए एक संदिग्ध यात्री के सामान की तलाशी ली गई। जहां पर जांच के दौरान उसके बैग में करीब 12 किलो गांजा बरामद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रग्स को जब्त कर आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि बरामद हाइड्रोपोनिक वीड उच्च गुणवत्ता की मादक पदार्थ श्रेणी में आता है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मांग है।

आरोपी से पूछताछ कर तस्करी के नेटवर्क और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार करोड़ों रुपये की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। इसके बावजूद तस्कर नए-नए तरीकों से मादक पदार्थों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।

कौन बनेगा बंगाल का नया सीएम? सुवेंदु के साथ 6 नेता भी मुख्यमंत्री की रेस में? शाह ने दे दिया हिंट

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की सियासत में दशकों बाद एक नया सूरज उगा है। ममता बनर्जी के 15 साल पुराने अभेद्य किले को ध्वस्त कर भारतीय जनता पार्टी (इखढ) ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक 'महाविजय' हासिल की है। अब राज्य की गलियों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है- "बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा?"

बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी भी चेहरे को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब जब पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिल चुका है, तो नामों की चर्चा तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही संकेत दे दिया था कि मुख्यमंत्री कोई 'बाहरी' नहीं, बल्कि बंगाल की माटी का ही लाल होगा। सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराकर दो सीटों पर जीते हैं, तो सीएम उम्मीदवार की रेस में उनका नाम सबसे पहले आर रहा है। लेकिन सुवेंदु अधिकारी से लेकर 'बंगाल के योगी' तक, आइए समझते हैं उन 7 चेहरों के बारे में जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।

1. सुवेंदु अधिकारीः 'जायंट किलर' और स्वाभाविक दावेदार

मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला और सबसे भारी नाम सुवेंदु अधिकारी का है। सुवेंदु ने इस चुनाव में वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जा रहा था। उन्होंने न केवल नंदीग्राम की अपनी सीट बचाई, बल्कि ममता बनर्जी के घर भवानीपुर में घुसकर उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया।

पार्टी सूत्रों की मानें तो सुवेंदु केवल नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह के निर्देश पर उन्होंने दोहरी चुनौती स्वीकार की। आज सुवेंदु बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। उनकी जमीनी पकड़ और ममता को सीधे चुनौती देने की क्षमता उन्हें इस पद का सबसे स्वाभाविक हकदार बनाती है।

2. समिक भट्टाचार्यः संगठन के माहिर खिलाड़ी

सुवेंदु के बाद दूसरा सबसे मजबूत नाम प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का है। समिक की सबसे बड़ी ताकत उनकी 'कोऑर्डिनेशन' क्षमता है। उन्होंने बंगाल के शिक्षित मध्यम वर्ग और पुराने-नए कार्यकर्ताओं के बीच एक पुल का काम किया। शाह के भरोसेमंद सुनील बंसल के मार्गदर्शन में समिक ने पार्टी के अंदरूनी कलह को शांत किया और सभी को एक छत के नीचे लाए। बंगाली संस्कृति और भाषा पर उनकी गहरी पकड़ है और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फ्रर) का भी मजबूत समर्थन हासिल है।

3. उत्पल महाराजः 'बंगाल के योगी' की एंट्री

इस रेस में सबसे चौंकाने वाला और चर्चा में रहने वाला नाम उत्पल महाराज का है। इन्हें 'बंगाल का योगी' कहा जाता है। उत्पल महाराज एक धार्मिक संस्था से जुड़े थे, जहाँ से इस्तीफा देकर उन्होंने कालियागंज सीट से चुनाव लड़ा और 76,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की।

हालांकि वो सामान्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच उतने चर्चित नहीं थे, लेकिन फ्रर और भगवा इकोसिस्टम के शीर्ष नेतृत्व में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। हिंदू मतों के ध्रुवीकरण में उनकी भूमिका को देखते हुए बीजेपी उन्हें 'सरप्राइज सीएम' के तौर पर पेश कर सकती है।

4. शंकर घोषः उत्तर बंगाल का युवा चेहरा

सिलीगुड़ी से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाले शंकर घोष को भी मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। शंकर घोष कभी सीपीएम के कट्टर कम्युनिस्ट नेता रहे हैं, लेकिन 2021 में बीजेपी में आने के बाद उन्होंने उत्तर बंगाल में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

एक कॉलेज प्रोफेसर के तौर पर उनकी छवि काफी साफ-सुथरी और बौद्धिक है। उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी ने दो-तिहाई से ज्यादा सीटें जीती हैं, ऐसे में शंकर घोष को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा।

5. दिलीप घोषः संघर्षों का प्रतीक

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बंगाल में पार्टी का आधार बनाने वाला नेता माना जाता है। उनके कार्यकाल में ही बीजेपी 2019 में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। खड़गपुर के इलाके में ओबीसी और अनुसूचित जातियों के बीच उनकी पकड़ बेजोड़ है। दिलीप घोष का बैकग्राउंड पूरी तरह से फ्रर का है। हालांकि वो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन संगठन में उनकी हैसियत आज भी एक वरिष्ठ मार्गदर्शक की है।

6. अग्निमित्रा पॉलः महिला नेतृत्व का उभरता चेहरा

बीजेपी अगर 'महिला मुख्यमंत्री' के कार्ड पर विचार करती है, तो अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे ऊपर होगा। जानी-मानी फैशन डिजाइनर रहीं अग्निमित्रा ने आसनसोल दक्षिण से अपनी जीत के साथ साबित किया है कि वो केवल ग्लैमरस चेहरा नहीं, बल्कि एक जुझारू नेता भी हैं। नेशनल मीडिया में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने वाली अग्निमित्रा को ममता बनर्जी के विकल्प के रूप में एक महिला सशक्तिकरण के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है।

7. स्वपन दासगुप्ताः बंगाल का बौद्धिक चेहरा

पूर्व पत्रकार और पद्म भूषण से सम्मानित स्वपन दासगुप्ता का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। स्वपन दासगुप्ता को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। दिल्ली की राजनीति में दशकों तक सक्रिय रहने के बावजूद वे अपनी बंगाली जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहे हैं। उनकी छवि एक पढ़े-लिखे और सभ्य बंगाली की है। बीजेपी उन्हें बंगाल के 'बौद्धिक समाज' के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री बना सकती है।

लखनऊ में कम हो गया बसों का किराया, इन यात्रियों को मिलेगा लाभ; नए रेट आज 6 मई से होंगे प्रभावी

(जीएनएस)।

लखनऊ। इलेक्ट्रिक एसी सिटी बसों का किराया राजधानी में कम हो गया है। कल बुधवार से इसका लाभ उन यात्रियों को मिलेगा जो शहर में सात किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करेंगे। सात से लेकर 54 किलोमीटर से अधिक के सिटी बसों के 11 तरह का किराया स्लैब बना है। हर स्लैब में पांच रुपये की कमी होगी। चार किलोमीटर तक 10 रुपये व 4.1 से सात किलोमीटर के 15 रुपये किराया यथावत रहेगा यानी कम दूरी तक आने-जाने वालों को पहले की तरह भुगतान करना होगा।

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की 50वीं

बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में सिटी बसों का किराया दूसरे चरण में कम करने का प्रस्ताव पास हुआ था। सिटी ट्रांसपोर्ट के प्रबंध निदेशक अमरनाथ सहाय ने बताया, किराये में दस प्रतिशत कटौती की गई है, उसे अब लागू किया जा रहा है। इसमें सात से 54 किलोमीटर से अधिक तक के स्लैब में बदलाव होगा।

उन्होंने बताया, शहर में राजाजीपुरम से जीपीओ, जीपीओ से पालीटेक्निक, उतरेटिया से इकाना स्टेडियम, उतरेटिया से अहिमामऊ और ट्रांसपोर्ट नगर से वृंदावन तक का किराया अब तक 25 रुपये रहा है, जो अब 20 रुपये होगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नगर से इकाना स्टेडियम का किराया 35 रहा है, जो अब 30 रुपये होगा। असल में सिटी ट्रांसपोर्ट ने दो साल पहले सिटी बसों के शुरूआती स्लैब का किराया घटाया था। चार किलोमीटर तक का किराया 12 से घटाकर 10 और 4.1 से सात किलोमीटर का किराया 20 से घटाकर 15 रुपये किया गया था। दूसरे चरण में किराया घटने से यात्रियों का आवागमन अब और आसान हो सकेगा।

अब इस तरह देना होगा किराया

दूरी (कि.मी.)	पहले	अब
7.1 से 10	25	20
10.1 से 13	30	25
13.1 से 16	35	30
16.1 से 20	40	35
20.1 से 24	45	40
24.1 से 30	50	45
30.1 से 36	55	50
36.1 से 42	60	55
41.1 से 48	65	60
48.1 से 54	70	65
54.1 से अधिक	75	70

राजधानी में चल रही सिर्फ 115 सिटी बसें

राजधानी में सिटी ट्रांसपोर्ट की 115 इलेक्ट्रिक एसी बसें 22 मार्गों पर चल रही हैं। शहर की 40 लाख की आबादी के लिए कम से कम 600 से अधिक बसें होना चाहिए। बसें कम होने के बाद भी यात्री नहीं मिल रहे थे इसीलिए किराया कम किया गया है। यात्री न मिलने की वजह समय पर बसें न मिलना है।

सुवेंदु अधिकारी की जीत में 'एसआईआर' का कमाल? नंदीग्राम-भबानीपुर के इन आंकड़ों ने उड़ाए होश! देख लीजिए जीत का गणित

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खी बनकर उभरे हैं बीजेपी के 'जायंट किलर' सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु ने न केवल अपने गढ़ नंदीग्राम को बचाया, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके घर भबानीपुर में घुसकर मात दे दी।

इस 'डबल विक्ट्री' के पीछे अमित शाह की सटीक रणनीति तो थी ही, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी प्रक्रिया ने काम किया जिसने जीत-हार का पूरा गणित ही बदल दिया। इस प्रक्रिया का नाम है SIR । आंकड़ों को करीब से देखें तो पता चलता है कि वोटर लिस्ट से कटे नामों और सुवेंदु की जीत के अंतर के बीच एक बेहद गहरा और चौंकाने वाला कनेक्शन है।

नंदीग्राम का गणितः

नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के पवित्र कर को 9,665 वोटों से हराया। लेकिन असली कहानी वोटर लिस्ट में छिपी है। नंदीग्राम में रक्रक की प्रक्रिया के दौरान कुल 8,206 वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। चुनाव से पहले यहां वोटरों की संख्या 2,74,621 थी, जो नाम कटने के बाद घटकर 2,66,415 रह गई।

दिलचस्प बात यह है कि सुवेंदु की जीत का मार्जिन (9,665) और हटाए गए नामों की संख्या (8,206) लगभग बराबर है। यहां सुवेंदु को 1,27,301 वोट मिले, जबकि पवित्र कर 1,17,636 वोटों पर सिमट गए। बाकी 10 उम्मीदवारों की तो जमानत तक जब्त हो गई। यह आंकड़ा इशारा करता है कि लिस्ट में हुए बदलावों ने नतीजों पर कितना बड़ा असर डाला है। नंदीग्राम सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा - SIR से पहले कुल वोटरः 2,74,621, SIR के बाद वोटर घटकरः 2,66,415, यानी 8206 नाम हटाए गए- अब नतीजे देखेंः सुवेंदु अधिकारीः 1,27,301 वोट, टीएमसी के Pabitra Kar: 1,17,636 वोट, जीत का अंतरः 9665 वोट, गौर करने वाली बात यह है कि कटे वोटरों की संख्या (8206) और जीत का अंतर (9665) लगभग बराबर है।